



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158]
No. 158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1985/चैत्र 8, 1907
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1985/CHAITRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

आदेश

का.आ. 274(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./85:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 218 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./78, तारीख 29 मार्च, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड, नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध तारीख 29 मार्च, 1978 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और बैस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 6-ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700013 को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार, ने अपनी यह राय होन पर कि लोकोहित में यह समीक्षा है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे 31 मार्च, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

रहने के लिए निर्देश जारी किए थे देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 234 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 28 मार्च, 1983, स. का. आ. 644 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 29 गिनम्बर, 1983 स. का. आ. 948 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 31 दिसम्बर, 1983, स. का. आ. 465 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 जून, 1984, और का. आ. 971 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984,

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोकोहित में यह समीक्षा है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1986 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1986 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2(25)/74-सी. यू. एम.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY
AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th March, 1985

ORDER

S.O. 274(E)|18A|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 218(E)|18A|IDRA|78, dated the 29th March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Alok Vanaspati and Plywood Limited, located at Calcutta, has been taken over for a period of five years with effect from 29th March, 1978, and the West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A, Raja Subhodh Mallick Square, 7th Floor, Calcutta-700013, was appointed as the authorised controller;

And, whereas, the Central Government, being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions for such continuance for a further period

upto and inclusive of the 31st March, 1985 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 234(E)|18A|IDRA|83, dated 28th March, 1983, S.O. 694(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th September, 1983, S.O. 947(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st December, 1983, S.O. 465(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, and S.O. 971(E)|18A|IDRA|84, dated the 29th December, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1986.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1986.

[File No. 2(25)|74-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.